श्री महाराज सिंह भारती: अपना स्टाक आप एक साल में बदलेंगे लेकिन जो आप अमरीका से ले रहे हैं वह आठ साल पुराना है।

श्री जगजीवन राम : मैंने यही कहा कि मैं समझता था कि माननीय सदस्य को अनाज रखने का कुछ तजुर्बा है। अगर अपने घर में अनाज खराब होता रहेगा तो उसको बेच ही देना पड़ेगा, चाहे रुपया कितना भी हो। हमारे पास बहुत स्टाक है और उसको हमें जल्दी निकालना है। मैं दन को आश्वासन देना चाहता हूं कि रुपये की कमी का कोई असर हमारे बफर स्टाक पर नहीं रहेगा।

Written Answers to Questions

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में विकास परियोजनायें

*66. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से एक विस्तृत रिपोर्ट मिली है, जिसमें इटावा जिले में कौशलपुरी, अशोकपुरी और महेवा की विकास परियोजनाओं के भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा बहुत बड़ी राशि के दुर्विनियोग और गबन का उल्लेख किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) तथा (ख): राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Satellite Station at Arvi (Poona)

*68. SHRI N.K. SANGHI:

SHRI RAMA CHANDRA VEERAPPA:

SHRI Y.A. PRASAD :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Atomic Energy Department has been entrusted to set up a Satellite Station at Arvi, near Poona;

(b) if so, what would be the estimated cost of the project; and

(c) by what time the project is proposed to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) The Department of Atomic Energy have been entrusted with the construction of the Satelllite Communications Earth Station at Arvi, which on completion will be operated by the Overseas Communications Service.

(b) Rs. 522 lakhs approximately.

(c) 31st October, 1969.

एक समान सिविल संहिता

*69. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
कुमारी कमला कुमारी :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी:

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित किये गये अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किये गये संकल्प की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें यह मांग की गयी है कि समूचे देश में एक समान सिविल संहिता के बारे में संविधान के अनुच्छेद को 44 अविलम्ब लागू किया जाये :

(ख) क्या उस सम्मेलन में भाग लेने वाली मुस्लमान महिलाओं ने भारत में इस्लामी कानूनों में संशोधन करके, जैसा कि तुर्की, ईरान और पाकिस्तान में किया गया है, बहुविवाह तथा ऐसी ही अन्य बुरी प्रथाओं से उन्हें मुक्ति दिलाये जाने की मांग की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यदि विवाह सम्बन्धी इस्लामी विधियों में ऐसे संशोधन भी कर दिये जाएं, जैसे कि तुर्की, ईरान और पाकिस्तान में किए गए हैं, तो भी विवाह सम्बन्धी कोई एक रूप संहिता नहीं बन सकती । इन देशों की यथा संशोधित विधियाँ विवाह और विवाह विच्छेद की हिन्दी विधि से तात्विक रूप से भिन्न है ।

Scheme of Customs Service in Agricultural Machinery for Farms

*70. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH:
SHRI SARJOO PANDEY :
SHRI P.C. ADICHAN :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :
SHRI BAL RAJ MADHOK :
SHRI D.C. SHARMA :
SHRI BENI SHANKER SHARMA :
SHRI BHOLA NATH MASTER :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal under consideration to organise a customs service in agricultural machinery for farms; and

(b) if so, the main features thereof and total cost involved therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) A scheme for the establishment of Agricultural Machinery Hiring Centres for the benefit of farmers has been drawn up for implementation during the 4th Five Year Plan.

(b) The scheme provides for establishment of Agricultural Machinery Hiring Centres in the different States during the 4th Plan, each centre having a number of crawler and wheeled tractors and other agricultural machinery depending upon the requirements of the area where the centres would be set up.

Each centre would have a workshop attached to it. The workshop would also undertake repairs of machines hired under the scheme as well as of other machines of cultivators on charge basis.

The centres would be organised and operated by Agro-Industries Corporations, wherever these have been set up. In the other States, State Governments may take up the scheme directly. It is proposed to set up 30 tractor hiring centres during the 4th Plan period and the number would be increased later based on experience. The scheme would be taken up in such of the States and areas where intensive cultivation and multiple cropping are developing at a fast rate. It will also be taken up in areas where mechanisation is needed and has to be popularised.

The cost of setting up of one Agricultural Machinery Hiring Centre would come to about Rs. 20.37 lakhs—Rs. 17.87 lakhs for machinery and equipment and Rs. 2.50 lakhs for buildings, etc. The scheme would be financed on 50% equity and 50% loan basis. The Central and State Governments would contribute in equal proportion towards the equity share capital of the Corporation. The loan would be provided by the Government of India to the State concerned depending upon the need of the State Corporations for loan assistance.

Seminar on Agricultural Finance

*71. DR. RAVEN SEN:
SHRI C. JANARDHANAN:
SHRI JAGESHWAR YADAV

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India had recently organised a seminar on agricultural finance in Bombay;